मजदूरों का अपना कोई देश नहीं होता ।

दुनियां के मजदूरो, एक हो !

फरीदाबाद मजदूर समाचार

मजदूरों की मुक्ति खुद मजदूरों का काम है ।

दुनियां को बदलने के लिए मजदूरों को खुद को बदलना होगा ।

RN 42233 पोस्टल रजिस्ट्रेशन L/HR/FBD/73

नई सीरीज नम्बर 53 | नवम्बर 1992 | 50 पैसे

नई राह

लाख डेढ़ लाख होते हुये भी फरीदाबाद की फैक्ट्रियों में ठेकेदारों के मजदूर और कैजुअल वरकर हताश-निराश रहे हैं। मैनेजमेंटों के हमलों में हाल में आई तेजी ने परमानेन्ट मजदूरों को भी हताश-निराश कर दिया हैं। इस स्थिति से उबरने के लिये मजदूरों द्वारा अपने-अपने अनुभवों के लेखे-जोखे लेना और एक-दूसरे को उनसे परिचित कराना जरूरी है। साथ ही, प्रत्यक्ष अनुभवों के ढेर में भटक जाने-खो जाने डूबजाने से बचने के लिये समाज और उसके प्रोसेस को समझने के प्रयास करने भी जरूरी हैं। दलदल से निकलने के लिये जरूरी नई राह के निर्माण की यह एक प्रक्रिया है। इस सम्बन्ध में लेख आमन्त्रित हैं।

जटिल तो है ही, विषय बहुत विस्तृत भी है। यहां हम फरीदाबाद के फैक्ट्री मजदूरों में तकिया कलाम-से बने नुक्तों पर प्रारम्भिक चर्चा से विषय को ओपन करेंगे।

"मजदूर के पास है ही क्या ? पैसे नहीं, लाठी-गोली नहीं, बुद्धि नहीं। मजदूर कुछ नहीं कर सकते।" एक सांस में यह और दूसरी ही सांस में, "मजदूर एक हो जायें तो कुछ भी कर सकते हैं। मैनेजमेंट-पुलिस- प्रशासन-दल्लों की धज्जियाँ उड़ा सकते हैं। पर मजदूर एक हो ही नहीं सकते।" यह ऐसी बातें हैं जो कि फरीदाबाद के फैक्ट्री मजदूरों में आम हैं।

"मजदूर कुछ नहीं कर सकते" के दबदबे ने झूठी आशाओं और खतरनाक निराशाओं के जँजाल में यहां मजदूरों को काफी समय से जकड़ रखा है।

अपने में से किसी को नेता बना कर उसकी ताकत के काल्पनिक किले बनाना अथवा किसी बाहरी नेता-झन्डे के सर्व-शक्तिशाली होने के सपने बुनना मजदूरों द्वारा खुद को कमजोर मानने की अभिव्यक्ति मात्र है।

इस सिलसिले में लगी हजारों हजार ठोकरों के कड़ये अनुभवों से यहाँ मजदूरों की यह आम समझ बनी हैं: "फरीदाबाद में सब नेता चोर हैं। यहाँ सब यूनियनें दुकान हैं।"

कोई और राह नजर नहीं आने पर परेशान मजदूर अब भी आधे-मन से बिचौलियों के पास जाते हैं पर नेताओं-झन्डों पर झूठी आशायें अब फरीदाबाद के मजदूरों पर कोई खास बोझ नहीं रह गई हैं। लेकिन "मजदूर कुछ नहीं कर सकते" वाली सोच का यहाँ मजदूरों के बीच दबदबा बना हुआ है। इससे पनपती खतरनाक निराशा अब यहाँ छँटनी और तनखा काट लेने तक पर मजदूरों की चुप्पी में अभिव्यक्त हो रही है।

जब-तब बनी अन्धी एकता में प्रदर्शित हुआ बल आज भी मजदूरों में कुछ उत्साह जगाता है। लेकिन भीड़ को अलौकिक शक्ति प्रदान करके उठे कदमों के दौरान लगी चोटों ने बिचौलियों के पुन: आगमन/पुन: उभार को तो जमीन प्रदान की ही, चोटों ने अपनी शक्ति में मजदूरों का जो थोड़ा-बहुत विश्वास है उसे डगमगाया भी है।

ठेकेदारों के मजदूरों और कैजुअल वरकरों को तो नई राह की जरूरत थी ही, परमानेन्ट मजदूरों के लिये भी नई राह एक अरजेन्ट आवश्यकता बन गई है। लेकिन जब तक मजदूरों के बीच इस सोच का दबदबा कायम है कि "मजदूर कुछ नहीं कर सकते", तब तक इस दिशा में सचेत कदम बहुत दूर तक नहीं जा सकते, शक्तिशाली नहीं बन सकते।

"प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या" सोच कर हजारों वर्ष तक पृथ्वी को चपटी और स्थिर समझने वाली बात कहीं "मजदूर कुछ नहीं कर सकते" पर भी लागु तो नहीं होती ? सोचिये। और हाँ, यह बात भी ध्यान में रखिये कि नक्षत्रों के अध्ययन ने पृथ्वी सम्बन्धी उन गलतफहमियों को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अपने बारे में अपनी शका, भ्रम, गलतफहमी दूर करने के लिये मजदूरों द्वारा समाज का अध्ययन आवश्यक है क्या ?

यह चर्चा आने वाले अंकों में जारी रहेगी।

खेतड़ी कापर प्रोजेक्ट

उत्तरी राजस्थान में खेतड़ी में केन्द्र सरकार की एक बड़ी ताम्बा परियोजना है। उस क्षेत्र से एक आन्दोलन की रिपोर्ट हमें प्राप्त हुई है।

१५ साल से लगातार काम कर रहे मजदूर भी खेतड़ी कापर प्रोजेक्ट में कैजुअल वरकर ही हैं। ठेकेदारी प्रथा का यहाँ बोलबाला है।

ताम्बा प्रोजेक्ट का गन्दा पानी आस-पास के खेतों में छोड़ दिया जाता है। इससे कुओं का पानी खराब हो गया है। पीने के पानी के खराब हो जाने से इलाके में स्वास्थ्य की समस्यायें बढ़ गई हैं। प्रोजेक्ट से निकलती गैसों से साँस की बीमारियाँ भी बढ़ गई हैं। जबकि नुक्सानदायक पदार्थों पर नियन्त्रण के लिये यहाँ लगाये गये यन्त्र काफी समय से बन्द पड़े हैं।

जिन लोगों की जमीनें खदान परियोजना के लिये सरकार ने ली थी उन्हें क्षतिपूर्ति के तौर पर प्रति परिवार एक व्यक्ति को नौकरी देने का आश्वासन भी दिया गया था। दसियों बरस बीत जाने के बाद भी ऐसे परिवारों में से अस्सी प्रतिशत नौकरी का इन्तजार ही कर रहे हैं।

ताम्बा परियोजना में बड़ी मात्रा में पानी इस्तेमाल होता है। गहरे-बिशाल ट्यूबवैलों के जरिये पानी प्राप्त किया जाता है। नतीजतन जल स्तर बहुत नीचे चला गया है। खेती वाले कूयें सूख-से गये हैं। प्रोजेक्ट के लिये नहर बना कर पानी लाने का प्रस्ताव था जिसे भुला दिया गया है।

इस सब के खिलाफ मजदूरों और किसानों का एक आन्दोलन इस समय खेतड़ी में चल रहा है। १८ सितम्बर को एक आमसभा के बाद आन्दोलनरत लोग जलूस की शक्ल में मैनेजमेंट से अपनी डिमान्डों पर बातचीत के लिये प्रोजेक्ट हैड आफिस पहुँचे। मैनेजमेंट टाल-मटोल करती रही। लोगों के डटे रहने पर रात ७½-८ बजे पुलिस ने लाठियों और आँसू गैस के गोलों से हमला किया। तीन घन्टों तक पुलिस ने घूम-घूम कर मजदूरों-किसानों पर लाठियाँ बरसाई। सौ लोग घायल हुये।

इस आन्दोलन में एक उल्लेखनीय बात यह भी सामने आई है कि खेतड़ी कापर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जिला प्रशासन और पुलिस, तथा एटक-सीटू समेत विभिन्न रंगों की ट्रेड यूनियनों ने इस मजदूर-किसान आन्दोलन के खिलाफ आपस में हाथ मिला लिये हैं। लेकिन मैनेजमेंट-यूनियन-पुलिस की आतंकवादी कार्रवाइयाँ उनके मनमाफिक रिजल्ट नहीं दे रही। बल्कि, क्षेत्र में उनके खिलाफ गुस्सा फैला हैं।

कापर प्रोजेक्ट के परमानेन्ट मजदूरों को आन्दोलन में शामिल करने के प्रयासों को प्राथमिकता देना इस आन्दोलन में मजदूर पक्ष की शक्ति बढाने के लिये तात्कालिक आवश्यकता लगता है।

कृषि टैक्नोक्रेटस

यहाँ बड़े पैमाने पर जमीन के टुकड़ों बँटे होने की वजह से खेती तो उद्योग की शक्ल कम ही ले पाई है पर मंडी के लिये प्रोडक्शन के सर्वव्यापी होने की वजह से खेती से जुड़े कई क्षेत्रों ने यहाँ भी उद्योग का रूप ले लिया है। नतीजतन केन्द्र व राज्य सरकारों के कृषि विभागों में गुणात्मक परिवर्तन हुये हैं/हो रहे हैं। इन हालात में हरियाणा कृषि टैक्नोक्रैट फैडरेशन जैसे संगठनों का उदय एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। हाल ही में, १९ से २३ अक्टूबर के दौरान हरियाणा कृषि टैक्नोक्रैट फैडरेशन के आन्दोलन के चौथे चरण में जिला मुख्यालयों पर धरने दिये गये। फरीदाबाद में भी यह कार्यक्रम हुआ।

हरियाणा के आन्दोलनरत कृषि टैक्नोक्रैट्स की मुख्यत: दो ही माँगें हैं:-

१. वेतनमान पंजाब के समान हो,

२. कृषि विभाग तकनिकी घोषित हो।

पहली माँग का उठाया जाना ही यहां के संविधान के "समान काम के लिये समान वेतन" के ढोंगी होने का एक और सबूत है।

दूसरी मांग एक पहलू से हकीकत का सही नामकरण करने की माँग है। पर कहीं यह शब्दावली उजरती गुलामी/वेज स्लेवरी पर बाबुई परदा न बन जाये इसके लिये यह ध्यान में रखना उपयोगी होगा कि कापट का इन्डस्ट्री बनते जाना इंजिनियरों, डाक्टरों, वैज्ञानिकों आदि को अधिकाधिक वेज वरकरस बना रहा है। इन क्षेत्रों में कार्यरत लोगों द्वारा उजरती गुलामी, वेज स्लेवरी को पहचानना, अपने मजदूर बन जाने की हकीकत से आँख मिलाना उनकी अपनीप्राथमिक जरूरत बन गई है।

पत्र

१. [पिछले अंक में हमने ग्वालियर में कपड़ा मजदूरों के गुस्से और कर्फ्यू का जिक्र भर किया था। विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त करने के प्रयास में हमें यह पत्र प्राप्त हुआ है।]

जे सी मिल (ग्वालियर) के घटनाक्रम को दिमाग में पिक्चर करना मैं भी चाहती थी। परन्तु मुश्किल रही। स्थानीय अखबारों से आपका काम नहीं चल सकता। चीटीभर काम की हाथीभर न्यूज छपवा देते हैं। मजदूर बस्ती में रहना ही सही तरीका है। दूसरा तरीका है तीन नेताओं से लम्बे इन्टरव्यू लेकर फिर सार और सिलसिला निकालना। इन दोनों तरीकों के लिये प्राथमिकता नहीं बन पाती।...

हाँ, हालत विस्फोटक है और मिल मजदूरों को जो जनसमर्थन मिल रहा है वह ७९ की हड़ताल या और किसी भी समय देखा सुना नहीं गया था। दूसरी बात पारम्परिक ट्रेड यूनियन नेतृत्व देने में एकदम अक्षम है। परन्तु नया क्या उभर रहा है मुझे ठीक जानकारी नहीं।...

२. [दिल्ली के एक बुजुर्ग मजदूर के पत्र से कुछ तथ्यों को देने के लिये हम उनके पत्र को संक्षिप्त करके छाप रहे हैं।]

हजारों मजदूरों की अनेक कुरबानियों से प्राप्त अधिकार एक-एक करके छिन गये। अनगिनत

शेष पेज दो पर

संपर्क – मजदूर लाइब्रेरी, आटोपिन, झुग्गीबाटाचौककेपास, एन. आई. टी. फरीदाबाद 121001

पायलटों की नीची उड़ान

अक्टूबर में इंडियन एयरलाइन्स पायलटों के खिलाफ इस व्यवस्था के समर्थक कलमघिस्सुओं ने बहुत हाय-तौबा मचाई। वजह ? इस व्यवस्था के संविधान सम्मत कानूनों की पूर्ति करते हुये इंडियन एयर-लाइन्स पायलटों ने अपनी डिमांडें हासिल करने के लिये ३० अक्टूबर से हड़ताल आरम्भ करने का नोटिस दिया था।

जहां कहीं, जब कभी मजदूर इस व्यवस्था के तहत बनाये नियमों के असुसार निर्धारित काम करना शुरू करते हैं मैनेजमेन्टें चीख पड़ती हैं। पायलटों द्वारा नियमानु-सार काम करना आरम्भ करने पर रेडियो-टीवी-अखबारों ने भी एयरलाइन्स मैनेजमेंट के सुर में सुर मिलाया। ऐसा क्यों होता है ? इसका कारण यह है कि आमतौर पर मजदूर नियमों द्वारा निर्धारित काम से भी अधिक काम करते हैं !

"पायलटों को कुचल दो, कुचल दो !" के समवेत स्वर में शामिल नवभारत टाइम्स का १६ अक्टूबर का सम्पादकीय पायलटों की मांगों की जानकारी से आम वेतन भोगियों को "दशहत" हो जाने का जिक्र करते हुये कहता है: "पायलटों को अभी महीने में करीब छब्बीस हजार रुपये मिल रहे हैं और उनकी मांग है कि इसे बावन हजार तक बढाया जाये।.. पायलटों को ऐसी भारी मांग रखने की हिम्मत अथवा प्रेरणा कहां से मिली ? खबर है कि ईस्ट-वैस्ट एयरलाइन्स नामक एक निजी संस्था अपने पायलटों को प्रतिमाह बावन हजार रुपये दे रही है।" आम वेतनभोगियों को इससे "दशहत" होने का एक कारण नवभारत टाइम्स जैसों का वह प्रचार भी है जो मजदूरों को अधिक प्रोडक्शन करने और रूखी-सूखी खा कर गन्दी बस्ती में सन्तोष करने की सलाह नित्य देता है। खैर।

मैनेजमेन्टों की ही तरह उनके समर्थक भी मजदूरों के हिस्से को असल से बहुत बढ़ा-चढ़ा कर बताते हैं। पर यह यहाँ साइड की बात हैं। अगर बावन हजार रुपये प्रतिमाह की डिमान्ड की बात सही है तो भी इंडियन एयरलाइन्स के पायलटों ने अधिक नहीं बल्कि कम की मांग की है। आज आमतौर पर फैक्ट्रियों में यहाँ प्रति मजदूर औसतन एक लाख रुपये प्रतिमाह का प्रोडक्शन वरकर करते हैं। और बदले में मजदूर पाते हैं हजार दो हजार रुपये महीना। ऐसे में मजदूरों की पचास हजार रुपये प्रतिमाह जैसी मांग भी इस व्यवस्था के दायरे में ही कैद रहती है। यह एक सुधारवादी मांग ही है जबकि उजरती गुलामी/वेज स्लेवरी/ध्याड़ी की बेड़ियों को तोड़ना अपनी मुक्ती के लिये मजदूरों की जरूरत है। इंडियन एयरलाइन्स के पायलटों ने इस बार भी नीची उड़ान ही भरी है। फिर भी, पायलटों द्वारा पैदा अक्टूबर की हलचल यहाँ अन्य मजदूरों को आँख मल कर देखने को प्रेरित करने वाली है।

पायलट पढ़े-लिखे जानकार मजदूर हैं। उन्होंने हड़ताल का समय-सूझ-बूझ के साथ चुना था: जाड़े में हवाई जहाजों से अधिक यात्री सफर करते हैं। ऐसे समय पर पायलट संक्षिप्त हड़ताल करके भी मैनेजमेंट को करोड़ों रुपये का नुकसान पहुँचा सकते हैं। ऐसे में इस बार फिर एयरलाइन्स मैनेजमेंट ने कुछ झुकने का फैसला किया और आंशिक समझौता हो गया। इस पर पायलटों ने हड़ताल का नोटिस १६ नवम्बर तक मुलतवी कर दिया है।

अमरीका के राष्ट्रपति की १९८० की राह पर चलने की सलाह एयरलाइन्स मैनेजमेंट को खुलेआम दी गई है। अमरीका में १९८० में एयर कन्ट्रोलरों की हड़ताल को कुचलने के लिये राष्ट्रपति ने इमरजेन्सी शक्तियों से सब एयर कन्ट्रोलरों को डिसमिस कर दिया था ओर एयर फोर्स का इस्तेमाल किया था।

इंडियन एयरलाइन्स के पायलटों द्वारा इस सब पर विचार करना और तद्नुरूप कदम उठाने जरूरी हैं। हमारे विचार से मजबूत कदम वहीं होंगे जो बृहद्तर मजदूर एकता और उजरती गुलामी के खात्मे की ओर ले जायेंगे।

एस्कोर्ट्स

फरीदाबाद में सैकड़ों छोटी फैक्ट्रियों में एस्कोर्ट्स का काम होता है। इनमें काम करते हजारों मजदूरों को आमतौर पर सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन भी नहीं दिया जाता स्वयं एस्कोर्ट्स के प्लान्टों में भी ठेकेदारों के मजदूरों और कैजुअल वरकरों की उल्लेखनीय तादाद है जो कि बहुत कम लागत पर अत्यधिक उत्पादन करती है। और फिर एस्कोर्ट्स के चौदह हजार परमानेन्ट मजदूर हैं जिन पर मैनेजमेंट-यूनियन एग्रीमन्टों द्वारा वर्क लोड बढाने का एक अटूट-सा सिलसिला चल रहा है। यह मुख्यत: इन सब का मिलाजुला असर है कि इन दस साल में एस्कोर्ट्स के कारोबार में चार गुणा वृद्धि हुई है, यह सालाना बारह सौ करोड़ रूपयों से अधिक हो गया है।

वर्क लोड बढाते वक्त आमतौर पर एस्कोर्ट्स के परमानेन्ट मजदूरों के वेतन में रूपयों की गिनती बढाई गई है। लेकिन रूपये की क्रय-शक्ति लगातार गिरती रही है। इसे हिसाब में रखने पर एस्कोर्ट्स के परमानेन्ट मजदूरों का वेतन भी भारत-भर में अन्य मजदूरों की ही तरह लगातार कम हुआ है। पार्ट टाइम, ओवरटाइम, पत्नी-बच्चों के दुकान पर बैठने की जड़ यहाँ है। और जहां तक सहूलियतों का सवाल है, ६०-७० साल पुराने कानूनों को देख कर मजदूर चौंक जायेंगे। खैर।

एस्कोर्ट्स मैनेजमेन्ट द्वारा स्थापित बिचौलिया ऐस्कोर्ट्स के परमानेन्ट मजदूरों के धुन्ध में लिपटे वेतन और सहूलियतों का एकतरफा प्रचार करके टाइम-ब-टाइम फरीदाबाद में काफी मजदूरों को गुमराह करने में सफल हुआ है। एस्कोर्ट्स के हाल के घटनाक्रम पर एक निगाह डालना इस सम्बन्ध में उपयोगी होगा।

फैक्ट्री/कम्पनी को आधार पर बोनस का आम रिवाज है। एस्कोर्ट्स में विभिन्न लिमिटेड कम्पनियों के होने के बावजूद बोनस आदि पर आल-एस्कोर्ट्स का दायरा-सा रहा है। लेकिन इस साल एस्कोर्ट्स में कमाल हुआ है। आल-एस्कोर्ट्स तो गया भाड़ में, प्लान्ट के आधार पर हिसाब भी चूल्हे के हवाले कर दिया गया है। एस्कोर्ट्स फस्ट प्लान्ट में डिपार्टमेन्टों के हिसाब से बोनस दिया गया है। फस्ट प्लान्ट की कुछ डिपार्टमेन्टों के मजदूरों के लिये २० प्रतिशत बोनस की घोषणा की गई और कुछ डिपार्टमेन्टों के मजदूरों के लिये ८.३३ प्रतिशत की। इतना ही नही, २० परसैन्ट वालों को दिवाली से पहले बोनस दे दिया गया और ८.३३ परसैन्ट वालों को दिवाली से पहले ५०० रुपये एडवान्स के रूप में दिये गये। एस्कोर्ट्स की मोटर साइकिल डिवीजन (राजदूत, II प्लान्ट) के मजदूरों को भी ८.३३ परसैन्ट बोनस की घोषणा की गई है और इन मजदूरों को भी दिवाली से पहले ५०० रुपये एडवान्स के रूप में दिये गये। एस्कोर्ट्स मैनेजमेन्ट की इस खतरनाक चाल पर बिचौलिये लीपापोती कर रहे हैं—एक्सग्रेशिया का राग अलाप रहे हैं।

फैक्ट्री की बजाय फैक्ट्री की डिपार्टमेन्टों के आधार पर बोनस की एस्कोर्ट्स मैनेजमेन्ट द्वारा दिखाई राह को अपनाने में अन्य मैनेजमेन्टें देर नहीं करेंगी। और अन्य फैक्ट्रियों में बिचौलियों से मजदूरों को यह उम्मीद नहीं करनी चाहिये कि वे एस्कोर्ट्स में बिचौलियों के रूख से भिन्न रूख अपनायेंगे। इस सम्बन्ध में विचार-तैयारी का समय अब हैं।

नई-नई मशीनें, मार्केट की दिक्कतें, फाइनैन्स टाइट आदि एस्कोर्ट्स के परमानेन्ट मजदूरों पर मैनेजमेंट के नये और बड़े हमलों की स्थितियों का निर्माण कर रहे हैं। ऐसे में बिचौलियों को गाली देने से कोई बात नहीं बनेगी। छाती-पीटना भी किसी काम नहीं आयेगा। सचेत संगठित कदमों के जरिये ही एस्कोर्ट्स के परमानेन्ट मजदूर आने वाले दिनों में मैनेजमेंट के बड़े हमलों का मुकाबला कर सकेंगे। इसकी तैयारी का समय अब हैं।

पत्र पेज १ का शेष

अत्याचार सहे पुलिस की लाठियां खाई, जेल के कष्ट सहे, नौकरियां गँवाई, सब कुछ बेकार हो गया।... ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या गलती हुई...

ए आई टी यूसी; आई एन टी यू सी: सी आई टी यू: बी यम एस या ऐसी ही एक दो पोलिटिकल यूनियनज के अतिरिक्त आज चारों ओर छोटी-छोटी अलग-अलग व्यवसाय की यूनियनज का जाल सा बिछ गया है।...

... कई यूनियनज ... बन्दर बाँट...किसी के नेता को मकान... किसी के भाई-भतीजे को नौकरी .. अस्थाई भर्ती २६ दिन के बाद मजदूर को निकाल दिया जाता है और एक सप्ताह हाथ-पैर जुड़वा कर फिर रख लिया जाता है... पहलवान टाइप व्यक्ति भर्ती . डन्ड पेलना और मजदूरों का सिर फोड़ना। भेड़ की खाल में भेड़िये नेताओं की चांदी...

बड़े संगठनों ने पता नहीं क्यों अपना रूख बदल लिया। २५-३० वर्ष पूर्व जलसे होते थे, साप्ताहिक सभायें...कार्नर मीटिंग होती थी।...

सरकार...मजदूरों के हाथ-पैर तोड़ने के लिये पुलिस, अधिकार छीनने के लिये न्यायालय और मजदूर विरोधी कानून बनाने के लिये संसद...

सुरभी इन्डस्ट्रीज

प्लाट ३१८ सैक्टर २४ स्थित सुरभी इन्डस्ट्रीज एक छोटी फैक्ट्री है। इस फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों में ५० परमानेन्ट थे। परमानेन्ट मजदूरों ने अपने हित में संगठित आवाज उठानी शुरू की। इस पर मैनेजमेंट ने काम की कमी दिखा कर परमानेन्ट वरकरों में से मुखर मजदूरों की छँटनी कर दी। साथ ही साथ मैनेजमेन्ट ने नये वरकर भरती किये। इस प्रकार सुरभी इन्डस्ट्रीज में १०० मजदूर इस समय काम कर रहे हैं।

काम की कमी वाली मैनेजमेंट की दलील को आप सफेद-काली-पीली-लाल, जो चाहें वह झूठ कह सकते हैं। सुरभी इन्डस्ट्रीज के सड़क पर धकेल दिये गये परमानेन्ट मजदूरों ने हरियाणा सरकार को बार-बार हकीकत बताई। लेकिन उनसे बहरा कोई नहीं होता जो सुनना नहीं चाहते और उनसे अन्धा कोई नहीं होता जो देखना नहीं चाहते। मजदूरों के पक्ष की जब कोई बात होती है तब सरकार अन्धी और बहरी, दोनों बन जाती है। सुरभी इन्डस्ट्रीज की छँटनी को हरियाणा सरकार ने नियमानुसार करार दिया है। इतना ही नहीं, मजदूरों की केस को लेबर कोर्ट को रेफर करने की मांग को भी चन्डीगढ़ में बैठे लेबर डिपार्टमेंट के साहबों ने यह कर रिजेक्ट कर दिया है कि केस रेफर करने लायक नहीं है।

कुछ साथियों की छँटनी कर दिये जाने के बाद भी सुरभी के मजदूर चुप नहीं हुये। इस पर मैनेजमेंट ने घरेलु जाँच वाले नाटक करके कुछ और मजदूरों को नौकरी से निकाल दिया। डिसमिस कर दिये गये इन मजदूरों ने आवेदन दिये कि उनके केस लेबर कोर्ट को फैसले के लिये रेफर किये जायें। हरियाणा सरकार ने इन मजदूरों के आवेदन को भी यह कह कर रिजेक्ट कर दिया कि केस लेबर कोर्ट को रेफर करने लायक नहीं हैं। जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले हाथी के दिखाने वाले दाँत हैं, मजदूरों की आँखों में धूल झोंकने वाली एक और जालसाजी हैं।

केसों को रेफर करने के मजदूरों के आवेदनों को थोक में रिजेक्ट किया जाना हरियाणा सरकार की पालिसी के तहत हो रहा है।

हालात से निपटने के लिये मजदूर पक्ष की ताकत बढाना ही एकमात्र राह है।

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक एवं सम्पादक शेरसिंह के लिए उत्तरांचल प्रिन्टर्स, फरीदाबाद से मुद्रित: